

फिलिस्तीनियों का प्रतिरोध का अधिकार और इज़राइल का आत्मरक्षा का दावा

7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए गाजा पट्टी में इज़राइल की सैन्य कार्रवाई ने भयानक विनाश और मानवीय क्षति पहुँचाई है। 61,200 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत - जिनमें से अनुमानित 80% नागरिक हैं - के साथ, राफाह जैसे पूरे शहर तबाह हो गए हैं, और गाजा की 80% बुनियादी ढांचा, जिसमें अस्पताल, स्कूल और जल प्रणालियाँ शामिल हैं, नष्ट हो गया है। इस आक्रामक कार्रवाई को पारंपरिक “युद्ध” के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। दो संप्रभु राज्यों के बीच सशस्त्र संघर्ष के बजाय, यह एक कब्जा करने वाली शक्ति द्वारा अपनी नियंत्रण वाली नागरिक आबादी पर हमला है। यह निबंध तीन परस्पर संबंधित कानूनी बिंदुओं पर तर्क देता है: (1) फिलिस्तीनियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कब्जे का विरोध करने का मान्यता प्राप्त अधिकार है; (2) इज़राइल, एक कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में, गाजा में अपनी सैन्य अभियान को उचित ठहराने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा का कानूनी रूप से दावा नहीं कर सकता; और (3) इज़राइल के कार्य अंतरराष्ट्रीय कानून के बार-बार और गंभीर उल्लंघन का गठन करते हैं, जिसमें अवैध कब्जा, रंगभेद (अपार्थेइड), और कानूनी मानदंडों की व्यवस्थित अवहेलना शामिल है।

फिलिस्तीनियों का कब्जे का विरोध करने का अधिकार

विदेशी कब्जे का विरोध करने का अधिकार अंतरराष्ट्रीय कानून में मजबूती से निहित है। यह आत्मनिर्णय के सिद्धांत से निकलता है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि (ICCPR), और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि (ICESCR) में निहित है। 1967 से पश्चिमी तट, पूर्वी यरुशलम, और गाजा में इज़राइली कब्जे के तहत रह रहे फिलिस्तीनियों के लिए यह अधिकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कई प्रस्तावों में प्रतिरोध की वैधता को स्वीकार किया है। प्रस्ताव 37/43 (1982) “स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय एकता और औपनिवेशिक और विदेशी प्रभुत्व और विदेशी कब्जे से मुक्ति के लिए लोगों के संघर्ष की वैधता को सभी उपलब्ध साधनों, जिसमें सशस्त्र संघर्ष भी शामिल है,” की घोषणा करता है। इसके अतिरिक्त, जिनेवा सम्मेलनों के प्रोटोकॉल I (1977) का अनुच्छेद 1(4) उन सशस्त्र संघर्षों को अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष के रूप में मान्यता देता है, जिनमें लोग विदेशी कब्जे या औपनिवेशिक प्रभुत्व का विरोध करते हैं, जिससे ऐसे संघर्षों को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) के तहत वैधता प्राप्त होती है।

हालांकि इज़राइल ने 2005 में गाजा से अपनी बस्तियों को औपचारिक रूप से वापस ले लिया था, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने जुलाई 2024 में अपनी सलाहकारी राय में पुनः पुष्टि की कि गाजा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कब्जा किया हुआ क्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि इज़राइल की इसकी सीमाओं, हवाई क्षेत्र और समुद्री पहुंच पर प्रभावी नियंत्रण है। यह कानूनी स्थिति फिलिस्तीनी लोगों के कब्जे का विरोध करने के अधिकार को सक्रिय करती है।

कब्जे वाले क्षेत्र के खिलाफ आत्मरक्षा का दावा करने में इज़राइल की अक्षमता

इज़राइल अक्सर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का हवाला देता है ताकि अपनी सैन्य कार्रवाइयों को आत्मरक्षा के रूप में उचित ठहराए। हालांकि, कब्जे वाले क्षेत्र के संदर्भ में यह कानूनी तर्क लागू नहीं होता। ICJ की 2004 की सलाहकारी राय **कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में दीवार के निर्माण के कानूनी परिणाम** में स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा केवल किसी अन्य राज्य द्वारा सशस्त्र हमले के जवाब में लागू होती है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा:

“चार्टर का अनुच्छेद 51... इस मामले में कोई प्रासंगिकता नहीं रखता, क्योंकि इज़राइल यह दावा नहीं करता कि उसके खिलाफ हमले किसी विदेशी राज्य के लिए जिम्मेदार हैं।” (ICJ, 2004, पैरा. 139)

इसके बजाय, एक कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में, इज़राइल चौथे जिनेवा सम्मेलन (1949) से बाध्य है, जो कब्जे वाली आबादी के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को नियंत्रित करता है। इनमें नागरिकों की सुरक्षा (अनुच्छेद 27 और 33), सामूहिक दंड का निषेध, और भोजन, पानी और चिकित्सा देखभाल जैसे आवश्यक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी (अनुच्छेद 49 और 55) शामिल हैं।

गाजा में इज़राइल की सैन्य आचरण इन जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है। 61,200 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत - जिनमें से अधिकांश महिलाएँ और बच्चे हैं - और 80% घरों, अस्पतालों और स्कूलों का विनाश, किसी भी वैध सुरक्षा तर्क के तहत उचित नहीं ठहराया जा सकता। 2007 से लागू गाजा की घेराबंदी और नाकेबंदी IHL के तहत सामूहिक दंड का गठन करती है और इसे संयुक्त राष्ट्र की गाजा संघर्ष पर तथ्य-खोज मिशन (2009) द्वारा निंदित किया गया और 2024 में एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा पुनः पुष्टि की गई।

विशेष रूप से निंदनीय था मई 2024 में राफाह पर हमला, जो **दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल** नरसंहार मामले में ICJ द्वारा जारी अंतरिम उपायों के बावजूद शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन ने 12 लाख फिलिस्तीनियों को विस्थापित किया और राफाह क्रॉसिंग - मानवीय सहायता के लिए मुख्य प्रवेश द्वार - को बंद कर दिया, जिससे मानवीय संकट और गहरा गया। गाजा के पर्यावरण और कृषि बुनियादी ढांचे का विनाश, जिसमें 80% वनस्पति, 70% कृषि भूमि, 47% भूजल कुएं और 65% पानी के टैंक शामिल हैं, चौथे जिनेवा सम्मेलन के अनुच्छेद 55 का उल्लंघन करता है, जो कब्जा करने वाली शक्ति को आबादी के लिए खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है।

बार-बार उल्लंघन और कानूनी मानदंडों का क्षरण

कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र (OPT) में इज़राइल की नीतियाँ अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन और कानूनी दायित्वों की अवहेलना का एक सुसंगत पैटर्न दर्शाती हैं, जबकि दूसरों को समान आचरण के लिए निंदा करती हैं। ये उल्लंघन तीन मुख्य क्षेत्रों में स्पष्ट हैं:

विस्तारवाद और अवैध बस्तियाँ

चौथे जिनेवा सम्मेलन के अनुच्छेद 49(6) के तहत, कब्जा करने वाली शक्ति की आबादी को कब्जे वाले क्षेत्र में स्थानांतरित करना निषिद्ध है। फिर भी, इज़राइल ने 2009 और 2020 के बीच पश्चिमी तट में लगभग 24,000 बसने वाली आवास इकाइयों के निर्माण को अधिकृत किया और बस्तियों के लिए पश्चिमी तट की 675,000 से अधिक दुनम भूमि को नियंत्रित करता है। इन कार्यों ने फिलिस्तीनी क्षेत्र को खंडित कर दिया है, जिससे भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की व्यवहार्यता कमजोर हो गई है।

ICJ की 2024 की सलाहकारी राय ने इन बस्तियों की अवैधता की पुनः पुष्टि की और इज़राइल को इन्हें नष्ट करने और सितंबर 2025 तक कब्जे को समाप्त करने का आदेश दिया। इसके अलावा, इज़राइल द्वारा साझा प्राकृतिक संसाधनों का असमान उपयोग, जिसमें पर्वत जलभृत के 90% जल आपूर्ति का शोषण शामिल है, कब्जे वाले क्षेत्रों में संसाधनों के शोषण पर IHL के निषेधों का उल्लंघन करता है।

मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में रंगभेद (अपार्थेइड)

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों - जिनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल (2022) और ह्यूमन राइट्स वॉच (2021) शामिल हैं - ने निर्धारित किया है कि इज़राइल की नीतियाँ अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत रंगभेद का गठन करती हैं। 1973 का अपार्थेइड कन्वेंशन और रोम संनियम का अनुच्छेद 7(2)(h) अपार्थेइड को एक नस्लीय समूह द्वारा दूसरे पर व्यवस्थित दमन के संस्थागत शासन के रूप में परिभाषित करते हैं।

इज़राइल का शासन इस परिभाषा को पूरा करता है:

- **दोहरी कानूनी प्रणालियाँ:** पश्चिमी तट में फिलिस्तीनी सैन्य कानून के अधीन हैं, जबकि यहूदी बसने वाले नागरिक कानून की सुरक्षा का आनंद लेते हैं।

- **जबरन विस्थापन:** हजारों फिलिस्तीनियों ने अपनी निवास अधिकार खो दिए हैं, और 35 से अधिक बेदुइन गाँव मान्यता प्राप्त नहीं हैं।
- **राष्ट्रीयता आधारित भेदभाव:** OPT में फिलिस्तीनी बिना नागरिकता के रहते हैं, उन्हें इज़राइली नागरिकता और एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य दोनों से वंचित किया गया है।

ICJ का 2024 का फैसला अपार्थेइड की पदवी को स्वीकार करता है, जिसमें व्यवस्थित प्रभुत्व और दमन को कानूनी रूप से स्थापित के रूप में उद्धृत किया गया है।

अंधाधुंध और असमान सैन्य बल

गाजा में इज़राइल का सैन्य आचरण बार-बार IHL के सिद्धांतों - भेदभाव, आनुपातिकता और आवश्यकता - का उल्लंघन करता है। रोम सैनियम के अनुच्छेद 8 के तहत विशिष्ट युद्ध अपराधों में शामिल हैं:

- **नागरिकों या नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना** (अनुच्छेद 8(2)(b)(ii))
- **असमान हमले** (अनुच्छेद 8(2)(b)(iv))
- **युद्ध की विधि के रूप में नागरिकों को भुखमरी** (अनुच्छेद 8(2)(b)(xxv))

उदाहरणों में शामिल हैं:

- 16 अप्रैल 2024 को अल-मघाजी शरणार्थी शिविर पर हवाई हमला, जिसमें 15 नागरिक मारे गए, जिनमें 10 बच्चे शामिल थे।
- अक्टूबर 2024 में अल-तबाईन स्कूल और शहादा अल-अक्सा मस्जिद पर बमबारी, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए।
- 217 पत्रकारों, 120 शिक्षाविदों और 224 मानवीय सहायता कार्यकर्ताओं की मौत, जिनमें 179 UNRWA कर्मचारी शामिल हैं।

ये कार्य गाजा के बड़े हिस्सों को रहने योग्य नहीं बनाते, जो नस्लीय सफाई और संभवतः नरसंहार के मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसा कि ICJ ने जनवरी और मई 2024 में उल्लेख किया।

दोहरे मानक और कानूनी अपवादवाद

अपने उल्लंघनों के बावजूद, इज़राइल नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रयोज्यता को चुनौती देता है। इज़राइली अधिकारी दावा करते हैं कि पश्चिमी तट और गाजा "विवादित" क्षेत्र हैं, न कि कब्जे वाले, और ICJ के फैसलों को गैर-बाध्यकारी मानते हैं। फिर भी, इज़राइल अक्सर अंतरराष्ट्रीय कानून का हवाला देता है ताकि दूसरों को निंदा करे, जैसे कि ईरान, हिजबुल्लाह, या स्वयं ICC। यह चयनात्मक पालन कानून के शासन को कमजोर करता है और सार्थक जवाबदेही को बाधित करता है, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त राज्य के वीटो द्वारा इज़राइल की निरंतर सुरक्षा को देखते हुए।

निष्कर्ष

गाजा में इज़राइल की सैन्य कार्रवाई, वैध आत्मरक्षा के कार्य से बहुत दूर, अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर और निरंतर उल्लंघन करती है। एक कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में, इज़राइल को उस आबादी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसे वह नियंत्रित करता है। फिलिस्तीनियों का कब्जे का विरोध करने का अधिकार अंतरराष्ट्रीय कानून में निहित है, हालांकि इस प्रतिरोध को मानवीय मानदंडों का पालन करना चाहिए। इज़राइल के व्यवस्थित उल्लंघन - जिसमें युद्ध अपराध, सामूहिक दंड, अपार्थेइड और विस्तारवाद शामिल हैं - तत्काल अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही की मांग करते हैं। ICJ के 2024 के फैसले, मानवाधिकार संगठनों के बढ़ते साक्ष्य के साथ, स्पष्ट करते हैं कि अशुद्धता को अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इज़राइल के कार्यों को अपवाद के रूप में नहीं, बल्कि आपराधिक के रूप में माना जाए - और जो इसमें सहभागी हैं, जिनमें विदेशी राज्य शामिल हैं, उन्हें नरसंहार संधि, रोम सैनियम और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के तहत समान रूप से जवाबदेह ठहराया जाए।